

रजिस्टर्ड नं ० पी०/ए०० रम० १४.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 31 मार्च, 1982/10 चैत्र, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

शिमला-171004, 30 मार्च, 1982

संख्या 1-8/82-वि. स.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 (1982 का विधेयक संख्या क्र 3) जो दिनांक 30 मार्च, 1982 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

राज कुमार महाजन,
सचिव

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982

(जैमा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कर्तिपय धन राशि के भूगतान की स्वीकृति और उनके विनियोग हेतु

विधेयक ।

भारत गणराज्य के तेतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1982 कहलाएगा।	संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां जनका जिओड एक अरब, तरेपन करोड़, पच्चीस लाख, पच्चीस हजार, छ: सौ पचास रुपए आता है निकाली जाए और उनका वित्तीय वर्ष 1981-82 की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु उपयोग किया जाए।	हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1981-82 के वर्ष के लिए 1,53,25,25,650 रुपए की और राशि निकालना ।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को निकालने और उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धन राशियों का विनियोग, द्वारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा।	विनियोग ।

अनुसूची
(दोखिए धारा 2 तथा 3)

मांग संख्या	सेवायें एवं प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		जोड़
			रुपये	रुपये	
2	राज्यपाल तथा मन्त्रि परिषद्	राजस्व	11,04,000	1,96,000	13,00,000
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	—	80,000	80,000
4	सामान्य प्रशासन	राजस्व	47,22,000	220	47,22,220
5	भू-राजस्व	राजस्व	37,50,000	—	37,50,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	राजस्व	16,59,000	800	16,59,800
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	राजस्व पूँजी	2,08,14,900 19,03,000	7,200 —	2,08,22,100 19,03,000
9	चिकित्सा तथा परिवार नियोजन	राजस्व पूँजी	50,38,800 58,37,000	61,200 1,45,100	51,00,000 59,82,100
10	लोक निर्माण	राजस्व	10,69,50,000	—	10,69,50,000
11	कृषि	राजस्व पूँजी	3,97,07,000 2,04,00,000	3,000 —	3,97,10,000 2,04,00,000
12	लघु सिचाई	राजस्व	72,00,000	—	72,00,000
14	पशु पालन तथा दुर्घट विकास	राजस्व	63,70,000	—	63,70,000
15	मत्स्य	राजस्व	1,12,000	—	1,12,000
16	वन	राजस्व	36,03,900	2,46,100	38,50,000
17	सड़कें तथा पुल	राजस्व पूँजी	2,44,00,000 2,09,08,000	— 1,97,000	2,44,00,000 2,11,05,000
18	आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	राजस्व पूँजी	76,09,000 54,00,000	— —	76,09,000 54,00,000
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा ज़ेले	राजस्व	16,16,000	1,330	16,17,330
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति राजस्व	—	87,28,000	—	87,28,000
			6,77,10,000	—	6,77,10,000
21	सामुदायिक विकास	राजस्व	1,20,97,000	100	1,20,97,100
22	सहकारिता	राजस्व पूँजी	10,74,500 12,00,000	24,500 —	10,99,000 12,00,000
23	खाद्य एवं पोपाहार	राजस्व पूँजी	1,80,13,000 1,07,00,000	— —	1,80,13,000 1,07,00,000
24	जल तथा विद्युत विकास	राजस्व	35,00,000	—	35,00,000
25	सिचाई, नावचालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	राजस्व	12,50,000	—	12,50,000

1	2	3	
		रुपये	रुपये
27	मडक परिवहन	राजस्व	4,58,000
28	पर्यटन	राजस्व	1,000
		पूँजी	4,97,000
29	थ्रम तथा रोजगार	पूँजी	2,37,000
30	आवास	पूँजी	43,17,100
31	नगर विकास	राजस्व	5,94,000
		पूँजी	16,00,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	राजस्व	1,09,86,000
		पूँजी	90,000
33	वित्त	राजस्व	1,29,30,000
		पूँजी	—
34	सरकारी कर्मचारियों को क्रृपण	पूँजी	1,06,78,90,000
		पूँजी	44,00,000
		जोड़	44,94,87,200
			1,08,30,38,450
			1,53,25,25,650

उद्देश्य तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निषिद्ध पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय पूरा करने के लिए त्रांकित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य को संचित निषिद्ध में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 को धारा (1) के अनु प्रस्तुत किया जाता है।

राम लाल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
30 मार्च, 1982

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग काइन नं 0 फिन-ए-सी (2) 35/81]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरस्तापित करने तथा सभा के विचार हेतु अभिस्ताव किया है।

[Authorised English Text of Himachal Pradesh Viniyog Vidheyak, 1982, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

Bill No. 3 of 1982.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1982

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the year ending on the 31st day of March, 1982.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-three Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1982. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of one hundred fifty three crores, twenty-five lakhs, twenty-five thousand, six hundred and fifty rupees towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year, 1981-82 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of this Act.

Issue of a further sum of Rupees 1,53,25,25,650 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the year 1981-82.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

1 No. of Vote	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		Total Rs.
		Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on the Consoli- dated Fund Rs.	
2	Governor and Council of Ministers (Revenue)	11,04,000	1,96,000	13,00,000
3	Administration of Justice (Revenue)	—	80,000	80,000
4	General Administration (Revenue)	47,22,000	220	47,22,220
5	Land Revenue (Revenue)	37,50,000	—	37,50,000
7	Police and Fire Protection (Revenue)	16,59,000	800	16,59,800
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research (Revenue)	2,08,14,900	7,200	2,08,22,100
	(Capital)	19,03,000	—	19,03,000
9	Medical and Family Planning (Revenue)	50,38,800	61,200	51,00,000
	(Capital)	58,37,000	1,45,100	59,82,100
10	Public Works (Revenue)	10,69,50,000	—	10,69,50,000
11	Agriculture (Revenue)	3,97,07,000	3,000	3,97,10,000
	(Capital)	2,04,00,000	—	2,04,00,000
12	Minor Irrigation (Revenue)	72,00,000	—	72,00,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development (Revenue)	63,70,000	—	63,70,000
15	Fisheries (Revenue)	1,12,000	—	1,12,000
16	Forest (Revenue)	36,03,900	2,46,100	38,50,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	2,44,00,000	—	2,44,00,000
	(Capital)	2,09,08,000	1,97,000	2,11,05,000
18	Supplies, Industries and Minerals (Revenue)	76,09,000	—	76,09,000
	(Capital)	54,00,000	—	54,00,000
19	Social Security, Welfare and Jails (Revenue)	16,16,000	1,330	16,17,330
20	Public Health, Sanitation and Water Supply (Revenue)	87,28,000	—	87,28,000
	(Capital)	6,77,10,000	—	6,77,10,000
21	Community Development (Revenue)	1,20,97,000	100	1,20,97,100
22	Co-operation (Revenue)	10,74,500	24,500	10,99,000
	(Capital)	12,00,000	—	12,00,000
23	Food and Nutrition (Revenue)	1,80,13,000	—	1,80,13,000
	(Capital)	1,07,00,000	—	1,07,00,000
24	Water and Power Development (Revenue)	35,00,000	—	35,00,000
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control (Revenue)	12,50,000	—	12,50,000
27	Road Transport (Revenue)	4,58,000	—	4,58,000
28	Tourism (Revenue)	1,000	—	1,000
	(Capital)	4,97,000	—	4,97,000
29	Labour and Employment (Capital)	2,37,000	—	2,37,000
30	Housing (Capital)	43,17,100	85,900	44,03,000

1	2	3
31	Urban Development (Revenue) (Capital)	Rs. 5,94,000 16,00,000
32	Other Administrative Services (Revenue) (Capital)	Rs. 1,09,86,000 90,000
33	Finance (Revenue) (Capital)	Rs. 1,29,30,000 1,41,00,000
34	Loans to Government Servants (Capital)	Rs. 1,06,78,90,000 44,00,000
	TOTAL	Rs. 44,94,87,200 1,08,30,38,450
		Rs. 1,53,25,25,650

शिमला-171004, 30 मार्च, 1982

संख्या 1-9/82-वि. स.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधयक, 1982 (1982 का विधेयक संख्यांक 4) जो कि दिनांक 30 मार्च, 1982 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरस्थापित किया गया है की एक प्रति सर्व साधारण की सूचनार्थ हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित की जाती है।

राज कुमार महाजन,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

(जैसा कि विधान सभा में पुरस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 1982-83 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए करिपय धनराशियां चुकाने और उनका विनियोग करने हेतु ।

विधेयक ।

यह भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1982 कहलाएगा ।

संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धनराशियां, जिनका जोड़ एक अरब, वेतालिस करोड़, तेहतर लाख, इकासी हजार रुपये है, निकाली जाये और वित्तीय वर्ष 1982-83 के पहले चार मास की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु उपयोग किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वर्ष 1982-83 के लिए 1,42,73,81,000 रुपये की राशि निकालना ।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन धनराशियों को निकालने और उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धनराशियों का विनियोग, धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और रेवाप्रों के लिए किया जाएगा ।

विनियोग ।

अनुसूची

(देखिए धाराएं 2 और 3)

पांग संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन	विधान सभा द्वारा दत्तमत	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		जोड़
			सभा पर प्रभारित	संचित निधि	
1	विधान सभा तथा निर्वाचन	राजस्व	₹0	₹0	₹0
			35,22,000	36,000	35,58,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्रि परिषद्	राजस्व	9,94,000	4,10,000	14,04,000
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	37,66,000	8,66,000	46,32,000
4	सामाज्य प्रशासन	राजस्व	1,95,34,000	4,03,000	1,99,37,000
5	भू-राजस्व	राजस्व	1,47,77,000	—	1,47,77,000
		पूँजी	4,13,000	—	4,13,000
6	आबकारी तथा कराधान	राजस्व	42,55,000	—	42,55,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	राजस्व	3,39,78,000	—	3,39,78,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	राजस्व	15,44,17,000	—	15,44,17,000
9	चिकित्सा तथा परिवार नियोजन	राजस्व	4,86,61,000	—	4,86,61,000
		पूँजी	93,75,000	—	93,75,000
10	लोक निर्माण	राजस्व	9,84,60,000	—	9,84,60,000
		पूँजी	50,83,000	—	50,83,000
11	कृषि	राजस्व	3,81,53,000	—	3,81,53,000
		पूँजी	91,32,000	—	91,32,000
12	लघु गिर्वाई	राजस्व	4,27,08,000	—	4,27,08,000
		पूँजी	92,33,000	—	92,33,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण	राजस्व	1,54,04,000	—	1,54,04,000
		पूँजी	17,21,000	—	17,21,000
14	पशु पालन तथा दुर्घट विकास	राजस्व	1,70,02,000	—	1,70,02,000
		पूँजी	57,33,000	—	57,33,000
15	मरम्म	राजस्व	13,93,000	—	13,93,000
		पूँजी	3,40,000	—	3,40,000
16	वन	राजस्व	3,99,06,000	—	3,99,06,000
		पूँजी	18,73,000	—	18,73,000
17	सड़कें तथा पुल	राजस्व	3,01,93,000	—	3,01,93,000
		पूँजी	7,47,15,000	—	7,47,15,000
18	आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	राजस्व	1,63,77,000	—	1,63,77,000
		पूँजी	55,61,000	—	55,61,000
19	सामाजिक सुरक्षा कल्याण तथा जेले	राजस्व	2,02,21,000	—	2,02,21,000
		पूँजी	49,03,000	—	49,03,000

1	2	3			
	रु०	रु०			
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	राजस्व पूँजी	8,81,04,000 2,61,83,000	— —	8,81,04,000 2,61,83,000
21	सामुदायिक विकास	राजस्व पूँजी	4,35,94,000 91,000	— —	4,35,94,000 91,000
22	सहकारिता	राजस्व पूँजी	78,85,000 70,16,000	— —	78,85,000 70,16,000
23	खाद्य एवं पोषणाहार	राजस्व पूँजी	1,81,32,000 4,02,00,000	— —	1,81,32,000 4,02,00,000
24	जल तथा विद्युत विकास	राजस्व पूँजी	33,32,000 4,75,33,000	— —	33,32,000 4,75,33,000
25	सिवाई, नाव चालन, जल निकास तथा वाहन नियन्त्रण	राजस्व पूँजी	27,36,000 66,30,000	— —	27,36,000 66,30,000
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	राजस्व पूँजी	54,00,000 7,66,000	— —	54,00,000 7,66,000
27	सड़क परिवहन	राजस्व पूँजी	5,16,000 22,00,000	— —	5,16,000 22,00,000
28	पर्यटन	राजस्व पूँजी	5,83,000 30,08,000	— —	5,83,000 30,08,000
29	श्रम तथा रोजगार	राजस्व पूँजी	46,91,000 33,000	— —	46,91,000 33,000
30	आवास	राजस्व पूँजी	16,00,000 54,10,000	— —	16,00,000 54,10,000
31	नगर विकास	राजस्व पूँजी	37,22,000 8,99,000	— —	37,22,000 8,99,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	राजस्व पूँजी	2,27,60,000 15,07,000	— —	2,27,60,000 15,07,000
33	वित्त	राजस्व पूँजी	2,03,78,000 —	4,69,05,000 19,89,32,000	6,72,83,000 19,89,32,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	राजस्व पूँजी	64,16,000	—	64,16,000
35	जन जातीय विकास	राजस्व पूँजी	6,20,27,000 1,25,13,000	— —	6,20,27,000 1,25,13,000
	जोड़		.. 1,17,98,29,000	24,75,52,000	1,42,73,81,000

उद्देश्य तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1982-83 के पहले चार मास के लिए अनुमति व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय, पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 व 204 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा नहोने तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 की धारा (1) व अनुच्छेद 206 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। मांगी गई राशि में वर्ष 1982-83 की नई स्कीमों के प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया है।

शिमला:
मार्च 30, 1982.

राम लाल,
मुख्य मन्त्री।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव
[क्रित विभाग फाईल संख्या-फिन-1-सी(1) 23/81]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरस्थापित करने तथा उस पर सभा के विचार हेतु अभिस्ताव किया है।

[Authorised English Text of Himachal Pradesh Viniyog (Lekhanudan) Vidhaik 1982 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Bill No. 4 of 1982

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1982

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year, 1982-83.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-three Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1982.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of One hundred forty two crores, seventy-three lakhs, and eighty one thousand rupees towards defraying several charges which will come in course of payment during the first four months of the financial year, 1982-83 in respect of the services specified in column 2 of the Schedule.

Withdrawal of rupee 1,42,73,81,00 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1982-83.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 No. of Vote	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		Total
		Voted by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
1	Vidhan Sabha and Elections	Revenue	35,22,000	Rs. 35,58,000
2	Governor and Council of Ministers	Revenue	9,94,000	14,04,000
3	Administration of Justice	Revenue	37,66,000	46,32,000
4	General Administration	Revenue	1,95,34,000	1,99,37,000
5	Land Revenue	Revenue	1,47,77,000	1,47,77,000
		Capital	4,13,000	4,13,000
6	Excise and Taxation	Revenue	42,55,000	42,55,000
7	Police and Fire Protection	Revenue	3,39,78,000	3,39,78,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	Revenue	15,44,17,000	15,44,17,000
		Capital	21,61,000	21,61,000
9	Medical and Family Planning	Revenue	4,86,61,000	4,86,61,000
		Capital	93,75,000	49,75,000
10	Public Work	Revenue	9,84,60,000	9,84,60,000
		Capital	50,83,000	50,83,000
11	Agriculture	Revenue	3,81,53,000 ⁽¹⁾	3,81,53,000
		Capital	91,32,000	91,32,000
12	Minor Irrigation	Revenue	4,27,08,000	4,27,08,000
		Capital	92,33,000	92,33,000
13	Soil and Water Conservation	Revenue	1,54,04,000	1,54,04,000
		Capital	17,21,000	17,21,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	Revenue	1,70,02,000	1,70,02,000
		Capital	57,33,000	57,33,000
15	Fisheries	Revenue	13,93,000	13,93,000
		Capital	3,40,000	3,40,000
16	Forest	Revenue	3,99,06,000	3,99,06,000
		Capital	18,73,000	18,73,000
17	Roads and Bridges	Revenue	3,01,93,000	3,01,93,000
		Capital	7,47,15,000	7,47,15,000
18	Supplies, Industries and Minerals	Revenue	1,63,77,000	1,63,77,000
		Capital	55,61,000	55,61,000
19	Social Security, Welfare and Jails	Revenue	2,02,21,000	2,02,21,000
		Capital	49,03,000	49,03,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply	Revenue	8,81,04,000	8,81,04,000
		Capital	2,61,83,000	2,61,83,000
21	Community Development	Revenue	4,35,94,000	4,35,94,000
		Capital	91,000	91,000
22	Co-operation	Revenue	78,85,000	78,85,000
		Capital	70,16,000	70,16,000
23	Food and Nutrition	Revenue	1,81,32,000	1,81,32,000
		Capital	4,02,00,000	4,02,00,000

1	2	3	Rs.	Rs.	Rs.
24	Water and Power Development	Revenue	33,32,000	—	33,32,000
		Capital	4,75,33,000	—	4,75,33,000
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control	Revenue	27,36,000	—	27,36,000
		Capital	66,30,000	—	66,30,000
26	Stationery and Printing	Revenue	54,00,000	—	54,00,000
		Capital	7,66,000	—	7,66,000
27	Road Transport	Revenue	5,16,000	—	5,16,000
		Capital	22,00,000	—	22,00,000
28	Tourism	Revenue	5,83,000	—	5,83,000
		Capital	30,08,000	—	30,08,000
29	Labour and Employment	Revenue	46,91,000	—	46,91,000
		Capital	33,000	—	33,000
30	Housing	Revenue	16,00,000	—	16,00,000
		Capital	54,10,000	—	54,10,000
31	Urban Development	Revenue	37,22,000	—	37,22,000
		Capital	8,99,000	—	8,99,000
32	Other Administrative Services	Revenue	2,27,60,000	—	2,27,60,000
		Capital	15,07,000	—	15,07,000
33	Finance	Revenue	2,03,78,000	4,69,05,000	6,72,83,000
		Capital	—	19,89,32,000	19,89,32,000
34	Loans to Government Servants.	Capital	64,16,000	—	64,16,000
35	Tribal Development	Revenue	6,20,27,000	—	6,20,27,000
		Capital	1,25,13,000	—	1,25,13,000
	Total	..	1,17,98,29,000	24,75,52,000	1,42,73,81,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly equal to 1/3rd of the estimated expenditure of Government of Himachal Pradesh for the financial year, 1982-83 pending the completion of the procedure prescribed in Articles 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 1982-83.

SIMLA:
The 30th March, 1982.

RAM LALL,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin-I-C (1)/23/81]

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1982 recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in, and consideration by, the Legislative Assembly of the said Bill.